

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | ಬೆಂಗಳೂರು और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



मुख्यमंत्री
जन आवास योजना

RERA REG. NO.: RAJ/P/2025/4228

<https://rera.rajasthan.gov.in/>



जयपुर में आवासीय फ्लैट्स

के द्वितीय चरण हेतु लॉटरी द्वारा आवंटन

📍 वाटिका इन्फोटेक सिटी,
अजमेर रोड, जयपुर



मुख्यमंत्री जन आवास योजना - 3A

के तहत जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एवं रेरा में पंजीकृत
नितल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एलएलपी द्वारा विकसित आवासीय योजना

90% तक लोन उपलब्ध
विश्वस्तरीय क्लब हाउस व स्विमिंग पूल

केन्द्रीय व राज्य कर्मचारियों, कॉर्पोरेट्स एवं प्रवासी राजस्थानवासियों के लिए
1 लाख रुपये तक की विशेष छूट।

नितल

स्टूडियो और 3 बीएचके अपार्टमेंट

आवेदन की अंतिम तिथि

24 जनवरी, 2026

उपलब्ध फ्लैट	पंजीकरण राशि	मूल कीमत
स्टूडियो फ्लैट	₹66,000	₹23.0 लाख*
3 BHK फ्लैट	₹96,000	₹44.0 लाख*



आवेदन हेतु SCAN करें
www.nitalcmjanawas.in



9785 30 7000
9772 51 1112

विकासकर्ता -
नितल
इंफ्राप्रोजेक्ट्स
एलएलपी

*Terms & Conditions Apply

कश्मीरी पंडितों के बिना घाटी अधूरी है, लोग उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं : महबूबा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जम्मू/भाषा। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है और घाटी के लोग बेसब्री से उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि कश्मीरी पंडितों के लिए विधानसभा की दो सीटें आरक्षित करना बेहतर होगा।

महबूबा ने गांधी नगर स्थित पीडीपी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा, कश्मीरी पंडितों को अपना फंसला खुद लेना होगा। हम उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके बिना घाटी अधूरी है। वह कश्मीरी पंडितों के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रही थीं जिनके घाटी से पलायन के 36 साल 19 जनवरी को पूरे हो गए और अपनी वापसी व पुनर्वास के लिए पिछले दो दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने हाल में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें बताया कि विधानसभा में समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत करने के



बजाय वे सीटें उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, उन्हें आने दीजिए, चुनाव लड़ने दीजिए। वे वोट मांगेंगे और मुसलमान उन्हें वोट देंगे। इसी तरह समुदाय एकजुट होगा। उन्होंने कहा, वे हमारे भाई हैं, और हम चाहते हैं कि वे सम्मान के साथ लौटें और हमारे साथ मिलकर रहें ताकि कश्मीर पूर्ण हो सके। मुफ्ती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी का एकमात्र एजेंडा संवाद और विकास के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शांति और समृद्धि की बहाली और इसके क्षेत्रों की एकता है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने पीर पंजाल और चिनाब घाटी को संभागीय

दर्जा देने के उनके प्रस्ताव को डिक्सन योजना से जोड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेका) और भाजपा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह मांग पूरी तरह से प्रशासनिक है और इसका उद्देश्य उपेक्षित क्षेत्रों का संतुलित विकास और बेहतर शासन सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा, पीडीपी का केवल एक ही एजेंडा है -- जम्मू कश्मीर में गरिमा और सम्मान के साथ शांति बहाल करना। आपसी संवाद होना चाहिए, जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में (पीडीपी संस्थापक) मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिखाया था, जब जम्मू कश्मीर के भीतर और

पाकिस्तान के साथ भी संवाद किया गया था।

पीर पंजाल (राजौरी और पुंछ) तथा चिनाब घाटी (रामबन, डोडा और कश्तवाड़) को संभागीय दर्जा देने के उनके प्रस्ताव को नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारुक अब्दुल्ला द्वारा 'डिक्सन' योजना से जोड़े जाने पर मुफ्ती ने कहा कि वह उनका सम्मान करती हैं और उन्हें जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा नेता मानती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वह भूल गए हैं कि उनके पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को इसी फॉर्मूले के लिए गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके

संस्थापक का एजेंडा हो सकता है, जिसके लिए उन्हें बर्खास्त किया गया और जेल भेजा गया। यह कभी भी हमारी पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता।

'डिक्सन' योजना एक ऐसा फार्मूला था जिसने सितंबर 1950 में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधान न्यायाधीश सर ओवेन डिक्सन ने प्रस्तावित किया था, जिसका उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर मुद्दे का समाधान करना था।

महबूबा ने भाजपा पर आरोप लगाया, उन्होंने लद्दाख को (2019 में) अलग करके महाराजा के पूर्ववर्ती राज्य को पहले ही नष्ट कर दिया है और जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, हम पीर पंजाल और चिनाब घाटी का कश्मीर में विलय नहीं करना चाहते, बल्कि जनता के हित में इन दोनों क्षेत्रों के लिए अलग-अलग संभाग का दर्जा चाहते हैं। भाजपा ने डिक्सन योजना को उस वक्त लागू करना शुरू किया जब उन्होंने दक्षिण कश्मीर के अंतर्गतनाम संसदीय क्षेत्र की सीमाओं को फिर से निर्धारित करते हुए उसमें पुंछ और राजौरी को शामिल कर लिया।

रुपया सात पैसे टूटकर 90.97 प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। रुपया मंगलवार को सात पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.97 (अस्थायी) के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। धातु आयातकों से डॉलर की मजबूत मांग और लगातार विदेशी पूंजी की निकासी से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि वैश्विक अनिश्चितता ने जोखिम से बचने की प्रवृत्ति को बढ़ा दिया है और उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव बनाए रखा है। इसके अलावा, विदेशी पूंजी की निकासी के कारण घरेलू शेयर

बाजार में सुस्ती भी इसकी एक वजह रही। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 90.91 प्रति डॉलर पर खुला। कारोबार के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.06 पर पहुंच गया। अंत में 90.97 (अस्थायी) प्रति डॉलर के अब तक के निचले स्तर पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट है।

रुपया सोमवार को 12 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.90 पर बंद हुआ था। रुपया इससे पहले 16 दिसंबर 2025 को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.93 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ था।

मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने

की प्रवृत्ति एवं विदेशी निवेशकों (एफआईआई) की लगातार निकासी से रुपया नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करता रहा और कारोबार के दौरान 91 के स्तर से नीचे फिसल गया। हालांकि, कमजोर डॉलर और भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप ने रुपए की तीव्र गिरावट को रोक। चौधरी ने बताया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के रुख को लेकर विदेशी पूंजी की निकासी और वैश्विक बाजारों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति से रुपए में नकारात्मक रुख रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा, व्यापार समझौते की बातचीत को लेकर अनिश्चितता रुपए पर दबाव डाल सकती है। हालांकि, कमजोर डॉलर और केंद्रीय बैंक के किसी भी हस्तक्षेप से रुपए को निचले स्तर पर समर्थन

मिल सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के हाजिर भाव के 90.70 से 91.25 के बीच रहने का अनुमान है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.91 प्रतिशत की गिरावट के साथ 98.48 पर रहा। घरेलू शेयर बाजार के मोर्चे पर सेंसेक्स 1,065.71 अंक टूटकर 82,180.47 अंक पर जबकि निफ्टी 353 अंक फिसलकर 25,232.50 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेट कूड का भाव 63.94 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) सोमवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,262.82 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।

अंतरिक्ष डेटा केंद्रों के लिए अगला बड़ा स्थान होगा : सिस्को

दावोस/भाषा। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सिस्को के अध्यक्ष एवं मुख्य उत्पाद अधिकारी जीतू पटेल ने कहा कि कृत्रिम मेधा और उन्नत कंप्यूटिंग के कारण विशाल डेटा केंद्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए दुनिया को बहुत जल्द अंतरिक्ष में डेटा केंद्र देखने को मिलेंगे।

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक से इतर 'पीटीआई-भाषा' के साथ बातचीत में पटेल ने कहा कि हरित डेटा सेंटर जल्द ही बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं लेकिन अगले कुछ वर्ष में बिजली जैसी बुनियादी ढांचे की बाधाओं से निपटने के लिए अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनते देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर की बात करें तो शीतलन की जरूरत बहुत अधिक होती है क्योंकि एक 'रैक' के कुल वजन का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा शीतलन अवसंरचना का होता है। पटेल ने कहा, अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा की

तीव्रता पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक होती है, जिससे शीतलन की लागत और आर्थिक अनुपात यहां की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर पर हो सकते हैं। उन्होंने कहा, ऊर्जा की उपलब्धता भी अधिक होती है, इसलिए उनके अनुसार साथ-साथ अंतरिक्ष में भी डेटा सेंटर विकसित किए जाएंगे।

सिस्को के अध्यक्ष ने साथ ही मानव इतिहास में कृत्रिम मेधा (एआई) को सबसे बड़ा वैश्विक बदलाव बताते हुए कहा कि यह हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देगी लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। पटेल ने कहा कि एआई से हर नौकरी का स्वरूप बदल जाएगा और हर कार्यप्रवाह में परिवर्तन आएगा। उन्होंने हालांकि आगाह किया कि अधिकतर लोग अल्पाधुनि में इन प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को बहुत अधिक आंकते हैं, जबकि दीर्घाधि में वे इसे बहुत कम आंकते हैं। पटेल ने तीन प्रमुख बाधाओं

बुनियादी ढांचा, विश्वास और डेटा की कमी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, पहली बाधा यह है कि हमारे पास पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है, कृत्रिम मेधा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया में पर्याप्त बिजली, कंप्यूटिंग एवं नेटवर्क बैंडविड्थ नहीं है। दूसरी बड़ी बाधा भरोसे की कमी है। भरोसे की कमी से मेरा मतलब यह है कि अगर आप इन प्रणालियों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आप इनका उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए सुरक्षा इन प्रणालियों को अपनाने के लिए अनिवार्य शर्त बन जाती है। पटेल ने कहा, फिर तीसरी बाधा हम डेटा की कमी को मानते हैं क्योंकि अब तक इन कृत्रिम मेधा मॉडल को मानव-निर्मित डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है जो इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। हालांकि इसके बावजूद इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानव-निर्मित डेटा की कमी होने लगी है।

आवेदन



गुवाहाटी में मंगलवार को कांग्रेस नेता रेकीबुद्दीन अहमद अपने समर्थकों के साथ असम विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी टिकट के लिए आवेदन देने के लिए राजीव भवन पहुंचे।

सोना पहली बार 1.5 लाख रुपए के पार, चांदी 20,400 रुपए उछली

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार को सोना मजबूत मांग आने से 5,100 रुपए की छलांग लगाते हुए पहली बार 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया जबकि चांदी ने 20,400 रुपए के उछाल के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया।

अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने कहा कि सोना दिल्ली में 5,100 रुपए की बढ़त के साथ 1,53,200 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गया। इसके साथ ही सोने ने 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का अहम मनोवैज्ञानिक स्तर भी पार कर लिया। सोना सोमवार को 1,48,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी की कीमतों ने भी स्थानीय सर्राफा बाजार में मजबूती दिखाते हुए नया उच्चतम स्तर छू लिया। सफेद धातु 20,400 रुपए यानी लगभग सात प्रतिशत बढ़कर 3,23,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गई।

सोमवार को चांदी की कीमतों में 10,000 रुपए की तेजी देखी गई थी, जिससे यह तीन लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गई थी। विदेशी बाजारों में भी सोना और चांदी की मांग में तेजी रही। फोरेक्स डॉटकॉम के आंकड़ों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना पहली बार 4,700 डॉलर प्रति औंस का स्तर के पार पहुंचा। सोने में 66.38 डॉलर यानी 1.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ कीमत 4,737.40 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी हाजिर चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया और 95.88 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, सुरक्षित निवेश की मांग और आभूषणों एवं निवेशकों से आने वाली लगातार मांग के कारण कीमती धातुओं में यह तेजी देखी जा रही है।

कलश यात्रा



हरिद्वार में मंगलवार को आदिवासी समुदाय के लोग हरिद्वार में गायत्री तीर्थ शान्तिकुंज के शताब्दी समारोह के मौके पर 'कलश यात्रा' में हिस्सा लेते हुए।

गुजरात ने भारत को गांधी, पटेल और मोदी के रूप में तीन महान शख्सियतें दीं : उपराष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने मंगलवार को कहा कि गुजरात ने भारत को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रूप में तीन महान शख्सियतें दीं हैं।

उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से निर्धारित होता है।

एक बयान के अनुसार, उपराष्ट्रपति ने यहां ऐतिहासिक गांधी आश्रम में हरिजन सेवक संघ के दौरे के दौरान महादेव देसाई

पुस्तकालय विस्तार का उद्घाटन किया और व्यक्ति व समाज के बीच पारस्परिक संबंध पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर अपने निर्माण में समाज की भूमिका को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज को कुछ लौटाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज की सेवा करना न केवल एक नैतिक दायित्व है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का भी मार्ग है।

राधाकृष्णन ने राष्ट्र के प्रति गुजरात के योगदान की सराहना की और उन तीन महान शख्सियतों के लिए आधार व्यक्त किया, जो गुजरात ने भारत को दिए हैं महात्मा गांधी जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, सरदार वल्लभभाई पटेल जिन्होंने

राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया, और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, जिन्होंने देश के विकास के लिए योगदान दिया।

बयान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति ने आश्रम के भीतर स्थित कस्तूरबा संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी 1930 और 1940 के दशक में दिल्ली की अपनी यात्राओं के दौरान रुके थे।

इस यात्रा को बेहद भावनात्मक बताते हुए, राधाकृष्णन ने कहा कि कस्तूरबा गांधी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला साधारण घर और रसोईघर समेत आश्रम के अन्य हिस्से देखना भारत के नेताओं द्वारा बिताए गए सातगीर्ण जीवन की सशक्त याद दिलाता है।



वृद्धि रफ्तार कायम रखने के लिए ट्रकों की नई श्रृंखला से उन्मीदें : टाटा मोटर्स सीईओ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। जीएसटी दरों में कटौती के बाद वाणिज्यिक वाहनों की मांग में आई तेजी का लाभ उठाने के मकसद से टाटा मोटर्स लिमिटेड इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन दोनों श्रेणियों में 17 ट्रकों का नया पोर्टफोलियो लेकर आई है। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी गिरीश वाघ ने मंगलवार को यह जानकारी दी। टाटा समूह की वाणिज्यिक वाहन कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रमुख ने पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा कि कंपनी अब इलेक्ट्रिक ट्रकों को अधिक बहन क्षमता के साथ पेश कर इस खंड में भी अपना विस्तार कर रही है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाए जाने के बाद अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में वाणिज्यिक वाहन उद्योग

में स्पष्ट सुधार देखा गया है।

वाघ ने कहा, सितंबर तिमाही से दिसंबर तिमाही के बीच इस उद्योग के कुल पंजीकरण में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि टाटा मोटर्स की बिक्री मात्रा करीब 29.4 प्रतिशत बढ़ी है। उन्होंने कहा कि कंपनी इस सकारात्मक रुझान का फायदा उठाने के लिए अगली पीढ़ी के 17 ट्रकों की नई श्रृंखला पेश कर रही है, जिसमें 'आई-मोए' (इलेक्ट्रिजेंट मॉड्यूलर इलेक्ट्रिक व्हीकल) संरचना पर आधारित इलेक्ट्रिक ट्रक भी शामिल हैं।

कंपनी कम दूरी वाले इलेक्ट्रिक अपूर्ति खंड में पहले से मौजूद है और भारी श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रकों की तरफ अपना विस्तार कर रही है। इलेक्ट्रिक ट्रकों के बारे में वाघ ने कहा कि सात टन से लेकर 55 टन तक की क्षमता वाले टाटा ट्रक्स डॉट ईवी पिछले कुछ वर्षों में ग्राहकों के साथ मिलकर विकसित किए गए हैं और अब तक 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक का परीक्षण

पूरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक ट्रक इस्पात, सीमेंट, रसायन, ई-कॉमर्स और वाहन कलपुर्जा जैसे क्षेत्रों को चरणबद्ध तरीके से अपने लॉजिस्टिक आधार को कार्बन-मुक्त करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने मध्यम एवं हल्के वाणिज्यिक वाहन खंड में नई डीजल इंजन श्रृंखला 'अजुरा' को भी पेश किया जो ग्राहकों को अधिक भार-वहन क्षमता, बेहतर ईंधन दक्षता और उन्नत सुरक्षा के जरिये बेहतर लाभप्रदता प्रदान करेगी। कंपनी ने तीसरी तिमाही में 1,15,577 वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री की जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 95,770 इकाइयों से 21 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स की वाणिज्यिक वाहन बाजार में कुल हिस्सेदारी बढ़कर 35.7 प्रतिशत हो गई, जबकि 28 टन से अधिक श्रेणी के भारी वाणिज्यिक वाहनों में हिस्सेदारी करीब 56.7 प्रतिशत रही।

भाजपा में अध्यक्ष की घोषणा पहले, फिर चुनाव का ऐलान, लेकिन वह भी नहीं हुआ: कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। कांग्रेस ने नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नया अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद सत्तारूढ़ दल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अध्यक्ष की घोषणा पहले कर दी गई और फिर चुनाव का ऐलान किया गया, लेकिन वह भी नहीं हुआ।

पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि भाजपा अध्यक्ष के चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं रही और चुनाव को प्रभावित करने का का मौका भी नहीं मिला।

नितिन नवीन को मंगलवार को औपचारिक रूप से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। उन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है।

इस बारे में पूछे जाने पर खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा, चुनाव



कहां हुआ है, इसे चुनाव क्यों कहा जाए? आपने अध्यक्ष पहले घोषित कर दिया और फिर कहा कि चुनाव होगा, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। ज्ञानेश कुमार गुप्ता इसके विरोध में इस्तीफा देना चाहते हैं क्योंकि

उनकी कोई भूमिका नहीं है, यह कुछ प्रभावित नहीं कर सके, कुछ हेरफेर नहीं कर सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वामी अविमुक्तवेश्वरानंद की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और प्रधानमंत्री एवं भाजपा के लोग 'बिग बायर' का गेम खेल रहे हैं।

वरअलन, प्रधानमंत्री मोदी ने नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी और कहा कि पार्टी से संबंधित मामलों में यह युवा नेता उनका 'बांस' होगा।



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बेंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित

5 आलाकमान के बुलावे पर दिल्ली जाऊंगा : सिद्धरामय्या

6 ग्रीन लैंड : ट्रप का बाल हट या राज हट...?

7 'इश्कां टे लेखे' मेरे लिए एक सपना है : ईशा मालवीय



फ़र्स्ट टेक

उडुपी के श्री कृष्ण मठ ने ड्रेस कोड लागू किया

उडुपी (कर्नाटक)/भाषा। कर्नाटक में उडुपी स्थित श्री कृष्ण मठ ने एक सख्त ड्रेस कोड लागू किया है, जिसके तहत पुरुष श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी कमीज उतारनी पड़ेगी, जबकि महिलाओं को 'शालीन और पारंपरिक परिधान' में आना होगा। परयाया शिरूर मठ द्वारा जारी यह निर्देश सोमवार, 19 जनवरी से प्रभावी हो गया है। पूर्व में, पुरुषों के लिए बिना कमीज पहने पूजा करने का नियम सिर्फ पूर्वाह्न 11 बजे से पहले होने वाली महापूजा में शामिल होने वालों पर लागू था।

निशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



केलाल मण्डेला, मो. 9828233434

बागी हुए जो

बैठ गए चुप वे सारे क्यों, जो नूतन कहने वाले थे।
दूर हो गए आज अचानक, जो हमदम रहने वाले थे।
मार गया उनको लकवा जो, हवा संग बहने वाले थे।
कर डाला विद्रोह उन्होंने, जो सब कुछ सहने वाले थे।।



‘अवैध प्रवासी और शहरी नक्सली राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अवैध प्रवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए मंगलवार को कहा कि ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें उनके संबंधित देशों में वापस भेजा जाना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) मुख्यालय में नितिन नवीन (45) को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने शहरी नक्सलियों और जनसंख्या असंतुलन को भी देश के सामने महत्वपूर्ण चुनौतियों के रूप में बताया।

मोदी ने कहा कि कुछ अमीर और ताकतवर देश, जो खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं,

■ दुनिया भर में कोई भी अवैध प्रवासियों को स्वीकार नहीं करता। यह आवश्यक है कि उनकी पहचान की जाए और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जाए।

■ भारत कभी भी अवैध प्रवासियों को अपने लोगों और गरीबों से संबंधित सेवाओं को लूटने की अनुमति नहीं देगा।

अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें देश से निकाल रहे हैं, और कोई उनके काम पर सवाल नहीं उठा रहा।

प्रधानमंत्री ने कहा, ये देश लोकतंत्र का झंडा लहराते हैं और खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं। दुनिया भर में कोई भी अवैध प्रवासियों को स्वीकार नहीं करता। यह आवश्यक है कि उनकी पहचान की जाए और उन्हें उनके देशों में वापस भेजा जाए। मोदी ने कहा, भारत कभी

भी अवैध प्रवासियों को अपने लोगों और गरीबों से संबंधित सेवाओं को लूटने की अनुमति नहीं देगा।

प्रधानमंत्री ने कुछ राजनीतिक दलों पर वोट बैंक की राजनीति के हित में अवैध प्रवासियों को संरक्षण देने और उन्हें पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हमें उनका पर्दाफाश करना होगा और उन्हें जनता के सामने बेनकाब करना होगा।

भारी गिरावट से निवेशकों के 9.86 लाख करोड़ डूब गए

नई दिल्ली/भाषा। वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजार में मंगलवार को भारी गिरावट आने से निवेशकों के 9.86 लाख करोड़ रुपए डूब गए। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 1,065.71 अंक यानी 1.28 प्रतिशत फिसलकर 82,180.47 अंक पर बंद हुआ। इस चौतरफा बिकवाली से बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार मूल्यांकन 9,86,093.96 करोड़ रुपए घटकर 4,55,82,683.29 करोड़ रुपए यानी 5.01 लाख करोड़ डॉलर रह गया। बीएसई पर सूचीबद्ध कुल 3,503 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई जबकि 780 शेयर चढ़कर बंद हुए और 119 अन्य अपरिवर्तित रहे।

मनरेगा को कमजोर कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं प्रधानमंत्री : राहुल गांधी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



रायबरेली (उप्र)/भाषा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सत्ता का केंद्रीकरण करने और गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर कर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है।

अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर उसका अपमान किया है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने हाशिए पर पड़े लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा वापस ले ली है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार का यह कदम लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है।

गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में मनरेगा को बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। हम मजदूरों के साथ खड़े हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी देश की संपत्ति को उद्योगपति गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी के हाथों में केंद्रित करना चाहते हैं।

‘चंद्रमा पर लौटने के प्रयासों के साथ अंतरिक्ष दौड़ जारी है’

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हुआ, क्योंकि यह वह देश है जहां उनके पिता का जन्म हुआ था।

गहरे नीले रंग के अंतरिक्ष परिधान और इसी थीम वाले केनवास के जूतों में विलियम्स (60) भारतीय युवाओं से भरे सभागार में जोरदार तालियों के बीच दाखिल हुईं और बाद में सहजता से दर्शकों के साथ बातचीत की।

अमेरिकी नौसेना की पूर्व कैप्टन विलियम्स का जन्म 19 सितंबर, 1965 को अमेरिका के ओहियो के

यूक्लिड में हुआ था। उनके पिता दीपक पंझा गुजराती थे और मेहसाणा जिले के सुलासन के रहने वाले थे, जबकि उनकी मां उर्सुलिन बोनी पंझा स्लोवेनिया की थीं।

बातचीत के दौरान, उन्होंने उस समय के अपने अनुभवों को भी साझा किया जब वह अंतरिक्ष में फंस गई थीं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए आठ दिवसीय मिशन विलियम्स के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गया था क्योंकि उनकी

बोइंग अंतरिक्ष उड़ान में समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं, जिसके कारण कक्षा में उनका प्रवास नौ महीने से अधिक तक बढ़ गया था।

उस अवधि के कुछ दृश्य स्क्रीन पर दिखाए गए, जिसमें आईएसएस के बहुसंरक्षितिक दल को थैक्सगिविंग, क्रिसमस और एक दल के सदस्य का जन्मदिन मनाते हुए दिखाया गया।

विलियम्स ने कहा, हम बहुत अच्छे गायक तो नहीं हैं, लेकिन हम अंतरिक्ष केक बना सकते हैं। उनकी यह बात सुनकर दर्शक हंस पड़े। उन्होंने कहा, आप एक समय में लगभग 12 लोगों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर देख सकते थे।

॥ श्री महावीराय नमः ॥
॥ श्री अम्बर-ज्येष्ठ-तारक-पुष्कर गुरुभ्यो नमः ॥ ॥ जय आत्मानंद देवेन्द्र शिव महेन्द्र ॥

फूलों की नगरी बेंगलूर में
राष्ट्रसंत, दक्षिण सभ्राट् उपपर्वतक पूज्य गुरुदेव **श्री नरेश मुनिजी म.सा.**, शासन रत्न गुरुदेव **श्री शालिभद्रजी म.सा.** की मंगलमय निश्रा में

अध्ययन रत जिनशासन प्रभाविका श्रमणीसूर्या उपपर्वतनी गुरु भां **डॉ दर्शन प्रभाजी म.सा.** द्वारा प्रेरित

अध्यात्म आराधक मुमुक्षु श्री लवेशजी सिंघवी का
जैनेश्वरी भागवती दीक्षा महोत्सव

जय गुरु नरेश

कर्म शत्रु को ध्वस्त, निरस्त करने हेतु एक उपकम

स्वर्णोत्सव निमंत्रण

जय गुरुजी ज्ञान, जय गुरुजी शालिभद्र, जय गुरुजी प्रतीभा, जय गुरुजी मल्ली, जय गुरुजी ताय, जय गुरुजी सुभा, जय गुरुजी मेधा, जय गुरुजी ब्रह्मि

प्रथम दिवस 21ST JAN 2026, WEDNESDAY
पाठ बिठाई : प्रातः 9:00 बजे से चौबीसी : दोपहर 2:00 बजे से

द्वितीय दिवस 22ND JAN 2026, THURSDAY
प्रवचन : प्रातः 9:00 बजे से मेहंदी-सांझी : दोपहर 2:00 बजे से

तृतीय दिवस 23RD JAN 2026, FRIDAY
केसर समारोह प्रातः 9:00 बजे से सांझी दोपहर 2:00 बजे से

चतुर्थ दिवस 24RD JAN 2026, SATURDAY
प्रातः 8:30 बजे से संयम शोभायात्रा (वर्षादान वरगोड़ा) पार्क वेस्ट से गुरुवन्ना देवरु मठ, प्रातः 09:30 बजे धर्म सभा में परिवर्तित होगी।

चतुर्थ दिवस 24RD JAN 2026, SATURDAY
दोपहर 2:00 बजे संयम संगीत बड़ी सांझी

पंचमदिवस, SUNDAY 25TH JAN 2026
बृहद् थाल मुबह 7:30 बजे महाभिनिष्क्रमण यात्रा मुबह 8:30 बजे दीक्षोत्सव प्रातः 9:00 बजे

नोट : पहले 3 दिन के कार्यक्रम श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर आराधना केन्द्र में एवं आखिरी दो दिन के कार्यक्रम गुरुवन्ना देवरु मठ में होंगे।
अल्पाहार एवं गौतम प्रसादी आराधना केन्द्र में ही रहेंगे।
शुभ स्थल : गुरुवन्ना देवरुमठ, ईटा गार्डन अपार्टमेंट के पास, बेंगलूर

दीक्षा महोत्सव के साक्षी बनकर संयम सफर के चश्मदीद गवाह बनें-सकल संघ के गौतम प्रसादी ग्रहण करने का आत्मीय निवेदन है।

निमंत्रक : श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन चेरिटेबल ट्रस्ट (रजि.) एवं आराधना केन्द्र, बेंगलूर

● श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन सेवा संगठन ● श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन महिला मंडल ● श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन युवती मंडल ● श्री गुरु ज्येष्ठ पुष्कर जैन बालिका मंडल



आदिवासी युवाओं को शिक्षा के बाद उच्च सरकारी पदों का लक्ष्य रखना चाहिए : बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को आदिवासी युवाओं से उच्च शिक्षा हासिल करने और उच्च सरकारी सेवाओं में प्रवेश करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समुदाय की तेज प्रगति के लिए यह जरूरी है। बागड़े ने मंगलवार को यहां लोकभवन में आदिवासी युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों से आए आदिवासी युवाओं से संवाद किया।

राज्यपाल बागड़े ने कहा कि ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और परस्पर विचार विनिमय की दृष्टि से युवा आदान प्रदान कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा के बाद उच्च सेवाओं में जाने के लिए परीक्षाएं देने और सफल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी युवा मन बनाकर उच्च शिक्षा, व्यवसाय और उच्च सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के प्रयास करें, इससे आदिवासी समाज तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

बागड़े ने युवाओं को नशे और व्यसन से दूर रहने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशा व्यक्ति को अशक्त करता है, उससे शारीरिक और मानसिक क्षमता का नाश होता है। उन्होंने भारत की संस्कृति को विश्व की प्राचीनतम संस्कृति बताते हुए कहा, विविधता होते हुए भी हमारी श्रद्धा और भक्ति एक है। भारत की संस्कृति मनो को जोड़ने वाली है। युवाओं ने आदिवासी संस्कृति से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। राज्यपाल ने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया।

सतत विकास के लिए इस्पात कबाड़ के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता : अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। देश को सतत विकास का समर्थन करने, उत्सर्जन कम करने और भविष्य के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन प्रक्रियाओं में इस्पात के कबाड़ के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने मंगलवार को कहा। 13वें अंतरराष्ट्रीय सामग्री पुनर्चक्रण सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (आईएमआरसी) को संबोधित करते हुए इस्पात मंत्रालय के संयुक्त सचिव दया निदान पांडे ने कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है। भारत ने पिछले चार वर्षों में तैयार इस्पात की खपत में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

उन्होंने कहा, भारत इस्पात के कबाड़ की हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ाए, ताकि सतत इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक औसत 31 प्रतिशत तक पहुंचा जा सके। मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरआई) द्वारा आयोजित सम्मेलन में पांडे ने कहा, यह बदलाव दीर्घकालिक ऊर्जा दक्षता हासिल करने, संसाधन सुरक्षा को समर्थन देने और इस्पात क्षेत्र के समग्र पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

उन्होंने बताया कि भारत का कबाड़ परिवेश अभी परिपक्वता के शुरुआती चरण में है। वैश्विक औसत तक पहुंचने में समय लगेगा। अधिकारी ने कहा, जैसे-जैसे भारत वित्त वर्ष 2030-31 तक 30 करोड़ टन और वित्त वर्ष 2046-47 तक 50 करोड़ टन इस्पात क्षमता लक्ष्यों की ओर बढ़ेगा, इस्पात कबाड़ सतत इस्पात उत्पादन में निर्णायक भूमिका निभाएगा।

पांडे ने कहा कि इस्पात क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग दो प्रतिशत का योगदान करता है और सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत वित्त वर्ष 2030-31 तक 30 करोड़ टन कच्चे इस्पात क्षमता का लक्ष्य रखा है। भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 14.43 करोड़ टन रहा। वर्तमान में कबाड़ का योगदान देश में कच्चे इस्पात उत्पादन का लगभग 21 प्रतिशत है। मटेरियल रीसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय मेहता ने कहा कि भारत में पुनर्चक्रण अब कोई परिधीय गतिविधि नहीं है, बल्कि संसाधन सुरक्षा, जलवायु प्रतिबद्धताओं और विनिर्माण प्रतिस्पर्धा का केंद्रीय हिस्सा है।

दो दिवसीय सम्मेलन में स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा भंडारण और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग वाली अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) की ओर बदलाव सहित विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।



राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मंगलवार को लोकभवन में प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग की कार्यशाला का समापन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस एससी विभाग की दो दिवसीय जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी संयुक्त कार्यशाला का पीसीसी में समापन हुआ। एससी विभाग प्रदेशाध्यक्ष ममता भूषे ने कार्यशाला में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को मनरेगा योजना बदलाव को लेकर चर्चा की और लोगों के बीच जाकर जनजागरण अभियान चलाने का आग्रह किया।

बैठक के दूसरे दिन जोधपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में भूषे ने मौजूद कांग्रेसजनों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने मनरेगा योजना में बदलाव कर गांव के करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर कुठाराघात किया है। महात्मा गांधी का नाम हटाकर नियमों में किए बदलाव से अब लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाएगा। लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे। प्रदेश के एससी समुदाय के लोग इस निर्णय से काफी ज्यादा प्रभावित होंगे।

भूषे ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सरकार में शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है। जनता इनके शासन से त्रस्त हो चुकी है और आगामी चुनावों में इनको उखाड़ फेंकने का मानस बना चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वे गांव गांव जाकर लोगों को मनरेगा में बदलाव दुरुपयोग कर जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं को जेल में डालने की कोशिश की जा रही है।

पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से इस सप्ताह राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार, राज्य के कुछ भागों में 22 से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने तथा मावठ की बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं एक और पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होगा। मौसम विभाग ने कहा कि 22 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 23 जनवरी को बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र व जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग के मुताबिक, 24-25 जनवरी को अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने तथा कहीं-कहीं घना कोहरा छाने का अनुमान है।

मंगलवार सुबह तक बीते चौबीस घंटे के दौरान राजधानी जयपुर में कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई लेकिन शेष राज्य में मौसम शुष्क रहा। कहीं-कहीं पर मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। इस दौरान अधिकतम तापमान जवाई बांध (पाली) में 30.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पाली में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जयपुर के पास हादसे में तीन व्यक्तियों की मौत

जयपुर। जयपुर के पास मंगलवार सुबह सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा उस समय हुआ जब एक कार अनियंत्रित होकर, सड़क के किनारे खड़े कंटेनर में जा चुसी। हादसा चंदवाजी थाना क्षेत्र में हुआ। थानाधिकारी हैरालाल ने बताया कि एक तेज रस्तरा कार अनियंत्रित होकर कंटेनर से जा टकराई। इस हादसे में एक महिला और दो पुरुषों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में दो बच्चों सहित छह लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार कार में सवार लोग बनारस की ओर जा रहे थे। मंगलवार को सुबह लगभग 11 बजे उनकी कार चंदवाजी पुलिसिया से एक किलोमीटर पहले एक खड़े कंटेनर से जा टकराई। पुलिस पीड़ितों की पहचान कर रही है।

गहलोत ने मणिपुर में राजस्थान की स्कूल टीम को बंधक बनाने की खबरों पर चिंता जताई

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय स्कूल खेलों के लिए मणिपुर गई राजस्थान की टीम को बंधक दिखा कर बंधक बनाए जाने की खबरों पर चिंता जताई है। गहलोत ने इस खबर को 'बेहद दुखद और चिंताजनक बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर लिखा, बेहद दुखद और चिंताजनक है कि राष्ट्रीय स्कूल खेलों के लिए मणिपुर गई राजस्थान की टीम को यहां पर बंधक की नोक पर बंधक बनाने एवं लूट की खबरें आई हैं। उनके अनुसार, बताया जा रहा है कि बच्चों और उनके परिजनों ने अपनी पीड़ा का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है। राजस्थान सरकार और खेल विभाग ने इस गंभीर मुद्दे पर क्या कार्रवाई की है? बच्चों के साथ ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और आईदा से राजस्थान से जाने वाली टीमों की सुरक्षा पुष्टा होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, मणिपुर पिछले करीब दो वर्षों से हिंसा और अशांति से जूझ रहा है। अब तो राष्ट्रपति शासन लागू है तो पूरी जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है लेकिन ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

विभाग ने इस गंभीर मुद्दे पर क्या कार्रवाई की है? बच्चों के साथ ऐसी घटना होना बेहद गंभीर है, मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और आईदा से राजस्थान से जाने वाली टीमों की सुरक्षा पुष्टा होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, मणिपुर पिछले करीब दो वर्षों से हिंसा और अशांति से जूझ रहा है। अब तो राष्ट्रपति शासन लागू है तो पूरी जिम्मेदारी भी केन्द्र सरकार की है लेकिन ऐसा लगता है कि केन्द्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।

तकनीक के प्रयोग से विभागीय कार्यों में बढ़ रही पारदर्शिता और शुद्धता : श्रीनिवास

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। भारतीय विदेश सेवा- 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में डिजिटलाइजेशन का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि तकनीक का प्रयोग राजकार्य की प्रक्रिया को न केवल सरल बनाता है, बल्कि इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता और शुद्धता भी आती है। प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नवीन विचारों और खोजपरक दृष्टि से आप जैसे युवा आमजन के जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने प्रदेश के बारे में बताया कि राजस्थान देश-विदेश में एक प्रसिद्ध पर्यटक विचारों और खोजपरक दृष्टि से आप जैसे



विधायिका भारतीय लोकतंत्र की धड़कन है : देवनानी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में मंगलवार को जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही विषय पर विधायिका को स्वयं का आत्म मूल्यांकन करने लोक और तंत्र के सेतु को सतत और सशक्त बनाने, नई चुनौतियों से मुकाबले के साथ भविष्य को प्रभावशाली बनाने के लिए दूरदर्शी उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव जनता का अडिग विश्वास होता है। यह विश्वास जनता से निरंतर संवाद, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण से ही कायम रह सकता है। देवनानी ने विधायिका को भारतीय लोकतंत्र की धड़कन बताया।

विधायी जनता को आकांक्षाओं का दर्पण - देवनानी ने कहा कि विधायिका कोई स्वतंत्र सत्ता-केंद्र नहीं, बल्कि जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का दर्पण है। सदन में बैठने वाला प्रत्येक सदस्य केवल स्वयं का नहीं, बल्कि लाखों नागरिकों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोकतंत्र की कसौटी यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और अधिकार पहुंचें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जवाबदेही केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि सदन के प्रत्येक सत्र, प्रत्येक बहस, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक विधायी हस्तक्षेप में दिखाई देनी चाहिए। एक जीवंत लोकतंत्र वही है जिसमें विधायिका जनता की समस्याओं को केवल सुनती ही नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से महसूस

को सुदृढ़ किया है तथा यह सुनिश्चित किया है कि समितियों की रिपोर्ट पर समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई हो। साथ ही सदस्यों के प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, बाल विधानसभा और यूथ पार्लियामेंट जैसी पहलों से भविष्य की पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ा जा रहा है।

आज डिजिटल जवाबदेही का युग - राजस्थान विधानसभा द्वारा उठाए गए डिजिटल नवाचारों के ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख करते हुए देवनानी ने कहा कि आज डिजिटल जवाबदेही का युग है। ऑनलाइन प्रक्रियाओं, पेपरलेस व्यवस्था, यूट्यूब पर कार्यवाही के सजीव प्रसारण और राजस्थान विधानसभा के डिजिटल म्यूजियम के माध्यम से पारदर्शिता को नई ऊँचाइयों पर ले जाया गया है। यह एक प्रकार का सोशल ऑडिट है, जो सदन को निरंतर सजग बनाए रखता है। देवनानी ने लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट और पोस्ट-लेजिस्लेटिव ऑडिट की आवश्यकता पर भी बल दिया, ताकि कानून बनने के बाद उनके वास्तविक प्रभाव का आकलन किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनता को नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनाना ही सच्ची जवाबदेही का उच्चतम रूप है।

पीठासीन अधिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का आसन केवल एक रेफरी का नहीं, बल्कि संविधान के संरक्षक का होता है। नियमों की व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिए कि वह चर्चा को रोकने वाली नहीं, बल्कि उसे विस्तार देने वाली हो। विधायिका को स्वयं का आत्म मूल्यांकन करना होगा, इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सदनों में सदस्यों की उपस्थिति विधेयकों के विविध पहलुओं पर चर्चा और सदन के भीतर संसदीय मर्यादाओं के पालन को विचारणीय बताया।



राजस्थान की उद्यमशीलता प्रवृत्ति को वैश्विक अवसरों में बदलें : राज्यपाल बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को कहा कि देश के औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले मध्यम उद्यम ही हैं। उन्होंने कहा कि इसी से लाखों परिवारों को रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। इसलिए इन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल ने 'राजस्थान इंडस्ट्री एंड एसएमई समिट' को मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में शुरू से ही उद्यमशीलता की प्रवृत्ति रही है। इस प्रवृत्ति को वैश्विक अवसरों में बदलते हुए भविष्य की असीम संभावनाओं के लिए मिलकर काम किया जाए।

उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों का ही सबसे बड़ा योगदान होगा।

आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने भारत के तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की चर्चा करते हुए कहा कि विश्व के 28 राष्ट्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश तेजी से सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। राज्यपाल ने भारत के उद्योगों को सशक्त

बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

बागड़े ने राजस्थान में अक्षय ऊर्जा एवं खनन से लेकर वस्त्र, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद और पर्यटन आदि क्षेत्रों की अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इनसे राजस्थान आने वाले वर्षों में बड़ा औद्योगिक राफ़्त बनेगा।

उन्होंने कहा कि आने वाला दशक भारतीय उद्योग के लिए अपूर्व अवसर लेकर आ रहा है और राजस्थान इस परिवर्तन के दौर में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। इससे पहले कार्यक्रम में राज्यपाल ने अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले श्रेष्ठ उद्यमियों को 'प्राइड ऑफ राजस्थान अवॉर्ड' से सम्मानित किया।

राजस्थान की उद्यमशीलता प्रवृत्ति को वैश्विक अवसरों में बदलें : राज्यपाल बागड़े

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने मंगलवार को कहा कि देश के औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले मध्यम उद्यम ही हैं। उन्होंने कहा कि इसी से लाखों परिवारों को रोजगार मिलता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। इसलिए इन पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। राज्यपाल ने 'राजस्थान इंडस्ट्री एंड एसएमई समिट' को मंगलवार को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में शुरू से ही उद्यमशीलता की प्रवृत्ति रही है। इस प्रवृत्ति को वैश्विक अवसरों में बदलते हुए भविष्य की असीम संभावनाओं के लिए मिलकर काम किया जाए।

उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों का ही सबसे बड़ा योगदान होगा।

आधिकारिक बयान के अनुसार, राज्यपाल ने भारत के तेजी से विकसित राष्ट्र बनने की चर्चा करते हुए कहा कि विश्व के 28 राष्ट्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश तेजी से सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन रहा है। राज्यपाल ने भारत के उद्योगों को सशक्त

बनाने के लिए सभी से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

बागड़े ने राजस्थान में अक्षय ऊर्जा एवं खनन से लेकर वस्त्र, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग उत्पाद और पर्यटन आदि क्षेत्रों की अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि इनसे राजस्थान आने वाले वर्षों में बड़ा औद्योगिक राफ़्त बनेगा।

उन्होंने कहा कि आने वाला दशक भारतीय उद्योग के लिए अपूर्व अवसर लेकर आ रहा है और राजस्थान इस परिवर्तन के दौर में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा। इससे पहले कार्यक्रम में राज्यपाल ने अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले श्रेष्ठ उद्यमियों को 'प्राइड ऑफ राजस्थान अवॉर्ड' से सम्मानित किया।



धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप दुआएं कमाते हो तो धन के साथ खुशी सेहत प्यार भी आता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

सद्भाव से मिटेगा भेदभाव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए जो सुझाव दिया है, उस पर अमल करने से समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। जाति एक ऐसी व्यवस्था है, जिसे हटाने और मिटाने के लिए कई लोगों ने संघर्ष किए, लेकिन इसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए। हाँ, समाज में सकारात्मक बदलाव जरूर आए हैं। पहले, जिस स्तर पर भेदभाव होता था, उसमें बहुत कमी आ गई है। इसका स्वागत होना चाहिए। किसी भी इन्सान को जाति, लिंग, रंग, भाषा, प्रांत आदि के नाम पर भेदभाव का सामना बिल्कुल न करना पड़े। सबको अपनी उन्नति के लिए समान अवसर मिलें। जहां तक जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात है, क्या इसके लिए जाति को खत्म कर देना ही एकमात्र विकल्प है? अगर हम सभी जातियों में सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए रास्ते खोज लें तो भेदभाव को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसी कोशिशें की थीं, जिनके बहुत अच्छे नतीजे निकले थे। पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी नहीं बहु आती थी, उसी गांव का एक परिवार, जिसकी जाति अलग होती थी, उसे अपनी बेटी मानकर गोद लेता था। उसे उतना ही प्रेम और सम्मान मिलता था, जितना घर की अन्य बेटियों को मिलता था। लोग उन रिश्तों को आखिरी सांस तक

निभाते थे। क्या हम पूरे देश में ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं कर सकते? जातिगत भेदभाव को कानूनी उपायों से एक हद तक दूर किया जा सकता है, लेकिन इसका उन्मूलन समाजिक स्तर पर सद्भाव से ही हो सकता है। समाज में एकता की भावना पैदा करने के लिए सभी जातियों को साथ लेना होगा। अगर हम कुछ जातियों को दिन-रात इस बात के लिए कोसते रहेंगे कि उनके पूर्वजों में से किसी ने गलत काम किया या तो इससे सद्भाव की स्थापना नहीं होगी।

नहीं है। हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जीने का हकदार है। सबको साथ लेकर चलेंगे तो समाज मजबूत होगा। स्थानीय स्तर पर ऐसे प्रयोगों को बढ़ावा देना चाहिए, जो भेदभाव के बंधनों को दूर करें। उदाहरण के लिए, विभिन्न जातियों के लोग पखवाड़े या महोत्सव में एक बार हर घर से अनाज, दाल और सब्जियां आदि लेकर सबके लिए भोज का आयोजन करें। रसोई के काम में सभी जातियों के लोग हाथ बंटाएं। खाना परोसते समय सभी जातियों के लोग सहयोग करें। इससे जातिगत भेदभाव को दूर करने में मदद मिलेगी। आज सोशल मीडिया पर भेदभाव को दूर करने के बजाय ऐसी सामग्री की भरमार है, जो विद्वेष को बढ़ावा देती है। कोई व्यक्ति एक जाति के खिलाफ गलत टिप्पणी कर देता है, जिसके बाद अन्य लोग झगड़ते रहते हैं। अगर गौर करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे कई अकाउंट विदेशों से संचालित होते हैं। उनका काम है— भारतवासियों में जाति के नाम पर लड़ाई-झगड़े करवाना। लोगों में फूट डालना कितना आसान है! यह दुर्भाग्य का विषय है। एक तरफ लोग याद करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालकर देश को गुलाम बनाया था, लेकिन दूसरी तरफ जब कोई व्यक्ति उकसावे वाली टिप्पणी करता है तो सामाजिक एकता की सारी बातें भूल जाते हैं। हमें विचार करना चाहिए— कहीं हम वही गलती तो नहीं कर रहे, जो अतीत में हुई थी? इक्कीसवीं सदी में किसी भी तरह के भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

ट्वीटर टॉक



राजरस्थान प्रदेक्ष कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री रफीक मंडेलिया जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईक्षर से आपके स्वस्थ, सुदीर्घ एवं खुशहाल जीवन की कामना करते हैं।

—गोविंदसिंह डोटारसा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने पर नितिन नबीन जी को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अपने अथक परिश्रम और समर्पण भाव से संगठन के दायित्वों को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है।

—गजेन्द्रसिंह शेखावत



धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार के राज में अगर सर्वोच्च संतों का यह हाल है, तो यह घोर पाप है। सत्ता के अहंकार में प्रशासन द्वारा माफी मांगने के बजाय संत को ही नोटिस थमाना 'विनाशकारी विपरीत बुद्धि' का प्रमाण है।

—अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

ज्ञान की अनंतता

ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो हर क्षण कुछ नया जानने के लिए उत्सुक रहते थे। प्रायः शीर्षस्थ बुद्धिजीवी और अन्य जिज्ञासु उनके पास पहुंचते और अपनी-अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते। प्लेटो भी उनसे कुछ न कुछ नई जानकारी लेने का प्रयास करते। एक दिन प्लेटो ने विज्ञान के एक शिक्षक की अध्यात्म संबंधी जिज्ञासा का समाधान करने के बाद उससे विज्ञान संबंधी कोई जानकारी ली। शिक्षक के चले जाने के बाद शिष्य ने कहा, 'सर! आप संसार के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक हैं। जब आप आगंतुकों से कुछ पूछते हैं, तो हमें 'ग्लानि' महसूस होती है। आप इतने बड़े ज्ञानी होने के बावजूद ऐसा क्यों करते हैं?' संत प्लेटो ने उसे समझाते हुए कहा, 'वस्तु, ज्ञान अथाह है। उसकी कोई सीमा नहीं होती। मेरा ज्ञान भी उतना ही सीमित है, जितनी समुद्र की एक बूंद। पूर्ण ज्ञानी होने का कोई दावा नहीं कर सकता। जो ऐसा करता है, वह झूठा और अहंकारी होता है।' शिष्य प्लेटो की निरभिमानता के समक्ष नतमस्तक हो गया।

बेंगलूरु | बुधवार | 21-01-2026

www.dakshinbharat.com /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

ग्रीन लैंड : ट्रंप का बाल हट या राज हट...?

ऋतुपर्ण दवे

मोबाइल : 8989446288

कभी लगता है कि ट्रंप तानाशाह हैं, कभी लगता है कि तुनकमिजाल। शायद अमेरीका वारियों को भी अब ट्रंप को समझ पाना मुश्किल हो रहा होगा। उन्हें चुनते वक्त भी ऐसा अंदाजा हरगिज नहीं रहा होगा। लेकिन, इतना तो समझ आ रहा है कि अपनी दूसरी पारी में ट्रंप दुनिया में सबसे अलग करने की नीयत से हर वो काम करने पर आमादा हैं जिससे उनकी चर्चा और धमक बनी रहे। हो सकता है कि वो ऐसा कुछ करें भी जिससे वो हीरो या विलेन कुछ तो बन जाएं। लेकिन लगता नहीं कि वो कभी अमेरीका के आदर्श राष्ट्र प्रमुखों में गिने जाएंगे!

उनका दर्द जब-तब उनके बयानों से झलकता भी है। शांति के नोबल पुरस्कार की होड़ में मात खाने के बाद ट्रंप एकाएक अशांतिपूर्ण हरकतों पर उतावला हो गए। उनकी टीस इसी बात से समझ आती है कि इस पुरस्कार के लिए खुद अपनी पैरवी करने वाले ट्रंप ने नाँव के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर को विड्डी लिख नोबेल नहीं मिलने की शिकायत तक कर दी। साथ ही यह भी लिखा कि कि 8 जंग रुकवाने के बावजूद उन्हें नोबेल नहीं मिला इसलिए उन्होंने अब शांति के बारे में सोचना छोड़ दिया है। शांति जरूरी है, लेकिन अब वह यह भी सोचेंगे कि अमेरिका के हित में क्या सही है। ग्रीनलैंड पर जबरन कब्जा की उनकी नीयत और कोशिशों की एक वजह नोबेल शांति पुरस्कार न मिलने की खीझ भी स्पष्ट समझ आती है। रूस और चीन के खतरे की दुहाई देकर ट्रंप नाटो सदस्य डेनमार्क के ग्रीनलैंड को हथियाने का जो धम भर रहे हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नाटो की एकता के साथ ही वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। ट्रंप की जिद कहीं या दादागिरी यह उनका दुनिया का तानाशाह बनने जैसा ही कदम कहलाएगा। देर-



सबेर इसका खामियाजा अमेरीका ही भुगतनेा क्योंकि वैश्विक मंच पर दुनिया का दारोगा कहलाने वाले मजबूत देश की विश्वसनीयता कमेगी। ग्रीनलैंड की ज़िद पर दुनिया भर में शांति के पक्षधर लोगों की समझाइश का भी ट्रंप पर कोई असर न पड़ना मामले को गंभीर बनाता है। ग्रीनलैंड में 1979 से स्व-शासन है। उसकी विदेश और रक्षा नीति नाटो संगठन का सदस्य देश डेनमार्क देखता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त भाग है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क सरकारों ने भी हमेशा कहा है कि ग्रीनलैंड न कभी पहले बिकाऊ था न आज है। नाटो देश भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दादागिरी कर कब्जा कर ले। खुद यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क और इटली ने भी ट्रंप के बयान की आलोचना की है। इतना ही नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर जवाब देने की बात भी कह ट्रंप को चेताया तक है। इससे ट्रांसअटलांटिक संबंध भी कमजोर होंगे। ट्रंप की नीयत तो अपने पहले ही कार्यक्रमाल में ग्रीनलैंड को खरीदने की थी जो तब भी पूरी नहीं हो पाई। आठ यूरोपीय देशों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर टैरिफ की धमकी को ये देश ट्रंप का ब्लैकमेल, समझ से परे और



अनुचित बता रहे हैं। ट्रंप की हरकतों से यूरोप और अमेरिका के सुरक्षा सहयोग संगठन नाटो के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह दिख रहा है। खुद 80 प्रतिशत अमरीकी भी नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बने क्योंकि इससे नाटो में दो फाड़ होगी जिसका फायदा चीन और रूस जैसे अमेरिका विरोधियों को मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि यूरोपीय संघ यानी ईयू ट्रंप के लगाए गए टैरिफ का जवाब देने में पीछे है। ईयू 27 यूरोपीय देशों का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। इन सभी देशों का रुख अमेरिका पर ट्रेड पाबंदियां लगाने का है जिस पर वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जबकि इनका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना है। ऐसी स्थिति में नाटो देश भी अमेरिका की मुखालफत करेंगे। हालांकि ईयू एक खास कानूनी हथियार के इस्तेमाल की सोच रहा है, जिसे ट्रेड

बाजूका' कहते हैं। इसका मकसद उन देशों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना है, जो यूरोपीय देशों पर जबरदस्ती आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ईयू सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में भी हैं। जाहिर है इससे दो पक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय तनाव बढ़ना ही है जिसमें अमेरिका के विरोध में कई होंगे। इन सबके लिए जिम्मेदार ट्रंप ही होंगे। ट्रंप की मौजूदा सनक की वजह ग्रीनलैंड है जो सैन्य रणनीतिक लिखाज से बेहद खास है। यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के मध्य अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच होने से मिड-अटलांटिक क्षेत्र में है।

यहां से यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी आसान है। हालांकि यहां अमेरिका का थुले एयर बेस पहले से है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी-चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ने से चिंतित अमेरिका ग्रीनलैंड पर अवसर पाकर भू-राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। दूसरी ओर ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रैयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार हैं। ये भविष्य की विशाल आर्थिक और तकनीकी सम्पदा है। अभी चीन का इन उत्पादों पर 70 से 90 प्रतिशत नियंत्रण है। यह निर्भरता अमेरीका कम करना चाहता है। वही भूभंडलीय ऊर्ष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए जलपोत मार्ग खुल रहे हैं। जब ग्रीनलैंड अमेरीका का होगा तो निश्चित तौर पर वह रूस-चीन की बढ़त रोकने में मददगार होगा। इसीलिए ट्रंप ग्रीनलैंड को अमरीकी सुरक्षा का फ्रन्ट लाइन मानते हैं। अब ट्रंप की नीयत चाहे जो वो उनका अंतर्गमन ही जाने लेकिन क्या नोबल का शांति पुरस्कार मिलता तो भी ट्रंप ऐसा करते? अब यह ट्रंप का बाल हट है या राज हट, वही जानें फिलाहाल ट्रंप दुनिया में खुद को तमाशा जरूर बना रहे हैं। देखना उनका खेल कब तक चलेगा।

चिंतन

बाल मुकुन्द ओझा

मोबाइल : 9414441218

चिली इस समय भयावह आपदा की चपेट में है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगल में लगी आग की चपेट में आकर अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। चिली फिलहाल भीषण लू की चपेट में है। जंगल की आग ने तबाही मचा दी है, जिसके वजह से वहां इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चला है। आग की वजह से अब तक 50 हजार से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। कई कस्बों में घर, गाड़ियां और पूरी बस्तियां जलकर खाक हो गईं। कार्डसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के एक अध्ययन में बताया गया कि पिछले दो दशकों में जंगलों में आग के हादसों में दस गुना वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जंगल में आग लगने के कई कारण होते हैं। इनमें गर्मी के अलावा ईंधन और आँकसीयन मुख्य कारक हैं। जंगल में पेड़ों के सूखे पतों और टहनियां ईंधन का काम करते हैं। एक छोटी सी चिंगारी हीट का काम करती है। ऐसे में अगर हवा तेज चल रही हो तो एक जगह लगी आग पूरे जंगल

चिली के जंगलों में आग ने मचाई तबाही

रहा है, जहां घरम मौसम, सूखा और बाढ़ की घटनाएं बढी हैं। फरवरी 2024 में सेंटियागो के उत्तर-पश्चिम में स्थित विना डेल मार शहर के पास एक साथ कई आग लगी थीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हादसे में 138 लोगों की मौत हुई थी। उस समय करीब 16 हजार लोग प्रभावित हुए थे। आग की वजह से अब तक 50 हजार से ज्यादा लोगों को बेघर होना पड़ा है। कई कस्बों में घर, गाड़ियां और पूरी बस्तियां जलकर खाक हो गईं।

कार्डसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के एक अध्ययन में बताया गया कि पिछले दो दशकों में जंगलों में आग के हादसों में दस गुना वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार जंगल में आग लगने के कई कारण होते हैं। इनमें गर्मी के अलावा ईंधन और आँकसीयन मुख्य कारक हैं। जंगल में पेड़ों के सूखे पतों और टहनियां ईंधन का काम करते हैं। एक छोटी सी चिंगारी हीट का काम करती है। ऐसे में अगर हवा तेज चल रही हो तो एक जगह लगी आग पूरे जंगल

को तबाह करने के लिए काफी है। अगर गर्मियों का मौसम है, तो सूखा पड़ने पर ट्रेन के पहिए से निकली एक चिंगारी भी आग लगा सकती है। इसके अलावा कभी-कभी आग प्राकृतिक रूप से भी लग जाती है। ये आग ज्यादा गर्मी की वजह से या फिर बिजली कड़कने से लगती है। जंगलों में आग लगने की ज्यादातर घटनाएं इंसानों के कारण होती हैं, जैसे आगजनी, कैम्पफायर, बिना बुझी सिगरेट फेंकना, जलता हुआ कचरा छोड़ना, माचिस या ज्वलनशील चीजों से खेलना आदि। जंगलों में आग लगने के मुख्य कारण बारिश का कम होना, सूखे की स्थिति, गर्म हवा, ज्यादा तापमान भी हो सकते हैं। इन सभी कारणों से जंगलों में आग लग सकती है।

दरअसल जंगलों की आग से न केवल प्रकृति झुलसती है, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारे व्यवहार पर भी सवाल खड़ा होता है। गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं। जंगलों में लगी आग से जान-माल के साथ-

साथ पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। पेड़-पौधों के साथ-साथ जीव-जन्तुओं की विभिन्न प्रजातियां जलकर खाक हो जाती हैं। जंगलों में विभिन्न पेड़-पौधे और जीव-जन्तु मिलकर समृद्ध जैवविविधता की रचना करते हैं। पहाड़ों की यह समृद्ध जैवविविधता ही मैदानों के मौसम पर अपना प्रभाव डालती है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ऐसी घटनाओं के इतिहास को देखते हुए भी कोई ठोस योजना नहीं बनाई जाती है। जंगलों में यदि आग विकराल रूप धारण कर लेती है, तो उसे बुझाना आसान नहीं होता है। कई बार जंगल की आग के प्रति स्थानीय लोग भी उदासीन रहते हैं। दरअसल हमारे देश में ऐसी आग बुझाने की न तो कोई उन्नत तकनीक है और न ही कोई स्पष्ट कार्ययोजना। विदेशों में जंगल की आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य होता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जंगलों की आग पर तत्कड़ दिखती करते हुए कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय और अन्य प्राधिकरण वन क्षेत्र में आग लगने की घटना को हल्के में लेते हैं। जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो किसी ठोस नीति की आवश्यकता महसूस की जाती है। लेकिन बाद में सब कुछ भुला दिया जाता है।

नजरिया

शांति का मुखौटा, सत्ता की रणनीति: ट्रंप का वैश्विक विरोधाभास

ललित गर्ग

मोबाइल : 9811051133

नोबेल शांति पुरस्कार की उत्कट अभिलाषा में डूबे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व और कार्यशैली वैश्विक राजनीति के लिए एक गहरी विडंबना एवं विरोधाभास बनकर उभरी है। शांति का मुखौटा बनने का उनका दावा जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही विरोधाभासी उनके कदमों का स्वरूप है। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में वे जहां शांति स्थापित करना भ्रम लेना चाहते हैं, वहीं उनके निर्णय, वक्तव्य और नीतियां अक्सर युद्ध, अशांति, भय और अस्थिरता को जन्म देती दिखाई देती हैं। यह कैसी शांति है, जो बमों की गूँज, प्रतिबंधों की मार और नफरत की भाषा के साथ चलती है? यह कैसा शांति-दूत होने का नाटक है, जिसमें मानवता का रक्त बहाता रहे और सत्ता अपने हित साधती रहे? गुटों में शांति स्थापना के लिए ट्रंप की प्रस्तावित योजना इसी विरोधाभास का नवीन उदाहरण है। इसे शांति से अधिक व्यापारिक सौदे की तरह प्रस्तुत किया गया, मानो दशकों से हिंसा, विस्थापन और अस्मिता के संकट से जूझ रहे लोगों का भविष्य किसी रिजल एस्टेट या आर्थिक पैकेज से तय किया जा सकता हो। अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, स्थानीय जनता की सहमति और जवाबदेही—इन सबको दरकिनार कर शांति थोपने की यह कोशिश बताती है कि ट्रंप की दृष्टि में शांति कोई नैतिक या मानवीय मूल्य नहीं, बल्कि शांति-प्रदर्शन और राजनीतिक लाभ का औजार है। इस तरह बमों के साथ में शांति का दावा डोकरीला ही है, जिसमें शांति का सौदा एवं सत्ता की भूख ही दिखती है। ट्रंप की कथित शांति योजना, शांति के नाम पर वर्चस्व की राजनीति ही है। ऐसा लगता है शायद अहिंसा के और कम हिंसा के है। ट्रंप संयुक्त राष्ट्र को अक्षम, पक्षपाती और नौकरशाही से ग्रस्त बताकर उसकी

अवहेलना करते रहे हैं, जबकि सच यह है कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं का ढांचा अनिवार्य है। शक्तिशाली देशों को जब यह ढांचा अपने अनुकूल नहीं लगता, तो वे उसे कमजोर करने लगते हैं—ट्रंप इसी प्रवृत्ति का मुखर चेहरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित नूतन वैश्विक शांति संस्थान का विचार अपने आप में जितना आकर्षक दिखता है, उतना ही असुरक्षा के नाप पर एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था खड़ी करने की कोशिश, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे स्वीकृत बहुपक्षीय ढांचे को दरकिनार करती हो, वस्तुतः शांति से अधिक सत्ता-केंद्रित वर्चस्व की आकांक्षा को उजागर करती है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जिस नेतृत्व की नीतियों का आधार हथियारों के निर्माण और बिक्री, सैन्य गठबंधनों के निर्माण, युद्ध की धमकियों और आर्थिक दंड के जरिये दुनिया पर दबाव बनाया रहा हो, वह अचानक शांति का नया संकेत कैसे बन सकता है? ट्रंप की राजनीतिक सोच में शांति किसी मानवीय प्रतिबद्धता का नहीं, बल्कि सौदेबाजी, नियंत्रण और लाभ का साधन प्रतीत होती है। इसलिए उनके प्रस्तावित शांति संस्थान की उपयोगिता पर गंभीर संदेह खड़ा होता है। बिना वैधता, जवाबदेही और वैश्विक सहमति के खड़ी की गई कोई भी संस्था शांति का वाकफ नहीं बन सकती; वह केवल शक्तिशाली देशों की इच्छाओं को थोपने का उपकरण या जरिया ही बनती है। इस संदर्भ में ट्रंप का यह प्रयास शांति की दिशा में एक ठोस पहल नहीं, बल्कि हिंसा-प्रधान नीतियों पर पदां जलाने और वैश्विक शासन व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक और षडयंत्र एवं कुपेक्षा ही दिखाई देता है।

ट्रंप की सोच में शांति का अर्थ संघर्षों का समाधान नहीं, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना है। कभी वे संयुक्त राष्ट्र के समानांतर इस तरह की एक कथित शांति-व्यवस्था खड़ी करने की बात करते हैं, तो कभी ईरान पर युद्ध की धमकी देते हैं। एक

ओर वे यूरोपीय देशों की तारीफ कर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं, दूसरी ओर उन्होंने देशों पर व्यापारिक प्रतिबंधों और सैन्य खर्च का दबाव डालते हैं। यह दोहरा आवरण और कथनी और करनी का बड़े वैश्विक अस्थिरता को बढ़ाता है। शांति की भाषा बोलते हुए हथियारों की बिक्री, सैन्य गठबंधनों का विस्तार और आर्थिक दंड—ये सब उनकी नीतियों के अभिन्न अंग रहे हैं। परिणामस्वरूप दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहां युद्ध की आहटें तेज हैं और मानवता अस्तित्व के मुहाने पर पहुंचती प्रतीत होती है। गाजा संकट के संदर्भ में यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि बिना वैधता, सहमति और जवाबदेही के थोपी गई शांति कभी स्थायी नहीं होती। यदि नागरिकों की सुरक्षा, जीवन की गरिमा और राजनीतिक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाए, तो कोई भी समझौता खोखला साबित होगा। ट्रंप का दृष्टिकोण इन मूलभूत सच्चाइयों को अक्सर अनदेखा करता है। आर्थिक वादों को राजनीतिक अधिकारों के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना एक खतरनाक भ्रम है, जो जमीनी वास्तविकताओं के बोझ से ढह जाता है। शांति तभी टिकाऊ हो सकती है जब उसमें स्थानीय लोगों की वास्तविक आवाज शामिल हो, उनके दुख-दर्द को समझा जाए और न्यायपूर्ण समाधान की दिशा में ईमानदार पहल हो। भारत को गाजा में शांति प्रयासों में शामिल करने का प्रस्ताव भी इसी जटिलता को उजागर करता है। भारत का कूटनीतिक इतिहास बहुपक्षवाद, संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका और द्विपक्षीय सिद्धांत के समर्थन से जुड़ा रहा है। भारत के इझाइल से अच्छे संबंध हैं, तो अरब देशों में भी उसकी विश्वसनीयता बनी हुई है। लेकिन यदि शांति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करती है, तो यह भारत की स्थापित कूटनीतिक परंपरा के अनुकूल नहीं होगा। भारत ने हमेशा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय द्वािपक्षीय और संवाद को प्राथमिकता दी है। ऐसे में ट्रंप-प्रेरित पहल में शामिल होना भारत के लिए भी एक नैतिक और रणनीतिक चुनौती बन

सकता है। वास्तव में ट्रंप की नीतियां एक ऐसे विश्व-दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती हैं, जहां शक्ति ही सत्य है और नैतिकता केवल भाषणों तक सीमित है। उनकी बयानबाजी में नफरत और विभाजन की छाया साफ दिखती है। आपरासन, नरल, धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर उनकी भाषा ने वैश्विक स्तर पर असहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जब विश्व का सबसे शक्तिशाली देश इस तरह का संदेश देता है, तो उसका असर सीमाओं से परे जाता है। युद्ध केवल गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता, वह विचारों और शब्दों से भी लड़ा जाता है। ट्रंप के शब्द अक्सर आग में घी डालने का काम करते रहे हैं।

आज दुनिया जिन संकटों से जूझ रही है—यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक, एशिया से अफ्रीका तक, उनमें कहीं-न-कहीं महाशक्तियों की स्वायत्तपूर्ण नीतियों की छाया है। ट्रंप का दौर इस प्रवृत्ति को और उग्र बनाता दिखाई दिया, जहां वैश्विक सहयोग के बजाय 'मे पहले' की मानसिकता हावी रही। शांति के नाम पर दबाव, सौदेबाजी और धमकी—यह त्रयी मानवता के लिए घातक है। जो नेता स्वयं को शांति का प्रतीक बताता है, उससे अपेक्षा होती है कि वह पुल बनाए, दीवारें नहीं; संवाद बढ़ाए, युद्ध नहीं; भरोसा पैदा करे, भय नहीं। इस तरह प्रश्न यही है कि क्या शांति पुरस्कार की आकांक्षा मात्र से कोई शांति-दूत बन सकता है? यदि जवाबदेही, सहमति और मानवीय मूल्यों के बिना शांति थोपने की कोशिश की जाए, तो वह शांति नहीं, एक नया संघर्ष जन्म देती है। ट्रंप की कार्यशैली इसी सच्चाई की गवाही देती है। आज जब मानवता युद्धों में अपने जीवन को खो रही है, तब शांति का ढोंग और भी क्रूर प्रतीत होता है। दुनिया को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो शक्ति के प्रदर्शन से नहीं, बल्कि करुणा, न्याय और बहुपक्षीय सहयोग से शांति की राह प्रदर्शित करे। अन्धश्रुति शांति मसीहा होने का यह नाटक इतिहास में एक विफल और खतरनाक प्रयोग के रूप में ही दर्ज होगा।

महत्त्वपूर्ण

Printed& Published by Devendra Sharma on behalf of owners M/s. New Media Company,6/4 , 1st floor, Cantonment station road, Bengaluru-51and printed at Dinasadur Printing Division, 116, Queens Road, Bengaluru-560052. Editor-Shreekanth Parashar. ("Responsible for selection of news under PRB Act). Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.RNI No. 58061/93. Regn No.: RNP/KA/BGS/2050/2015-2017 posted at Bengaluru PSO Mysore Road Bengaluru-560 026

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वरीकृत, टैंडर एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी यह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रण एवं प्रकाशक या मालिकाना को पाठक किसी भी रूप में उत्तरवादी नहीं बना सकते। — दक्षिण भारत राष्ट्रमत

HEAD OFFICE : DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT, New Media Company, 6/4, Cantonment Station Road, Bangalore 560051. Editorial : 080-25363030 / 9945488003. For Advertisement : 9945488002 - email : news@dakshinbharat.com / **RNI No. 58061/93**